

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 67/18

GCMS NO 2018/00213

गोविन्द पि.मु.बृजलाल जाति मीना निवासी कुआगांव तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर
अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वामनवास
2. सहकारी भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रबंधक

रेसपो

(अपील विरुद्ध मु0नं0 74/17 निर्णय दिनांक 27.3.18 न्यायालय उप जिला कलेक्टर
वामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम


अभिभाषक रेसपो पैरोकार सरकार

दिनांक 15.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.3.18
न्यायालय उप जिला कलेक्टर वामनवास पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा
एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 69 रकबा
4 बीघा 19 विस्वा ग्राम कुआगांव तहसील वामनवास में स्थित है। जिसके हाल ख0न0 163 रकबा
0.09 है0 बना है। जबकि साबिक रकबा 4 बीघा 19 विस्वा की मैट्रिक सिस्टम में 1.24 है0 भूमि
बनती है। जिसका प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी को साबिक रकबे के मुकाबले 15 ऐयर भूमि कम दी
गई है। कम 15 ऐयर भूमि को आराजी ख0न0 73 रकबा 0.13 है0 , 74 रकबा 0.12 है0, 162
रकबा 0.27 है0 को चारागाह में दर्ज कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी की भूमि को मिला दिया गया
है। प्रार्थी की भूमि जो हाल ख0न0 73,74,162 में मिलाकर चारागाह दर्ज किया गया है जो प्रार्थी
की कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी की जो 15 ऐयर भूमि कम मिली है उसे चारागाह की भूमि में
मिला रखा है। जिससे ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर उक्त भूमि से रास्ता बनाना
चाहती है। जबकि उक्त भूमि में होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे
काश्त की है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की भूमि में से रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त
नहीं है। परन्तु वह जबरदस्ती रास्ता निकालने पर आमादा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अर्ज है कि गैरसायलान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द
फरमाया जावे कि प्रार्थी की भूमि आराजी ख0न0 163 रकबा 1.24 है0 में जो 15 ऐयर भूमि ख0न0
73,74 व 162 में मिली हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई रास्ता का निर्माण नहीं करावे तथा प्रार्थी
को उक्त भूमि में कब्जे काश्त में एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे। इस प्रकार की
इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा
प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आशय का स्वीकार किया गया कि आराजी ख0न0 73,74 व


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

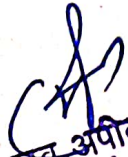


162 मे. से 15 ऐयर भूमि मे किसी प्रकार के रास्ते का निर्माण कार्य नही करावे साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि उक्त ख0नम्बरान मे से 15 ऐयर भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि से प्रार्थी का अतिक्रमण हटाया जावे तथा मूल वाद मे यदि प्रार्थी/अपीलांत 15 ऐयर भूमि पर अपना स्वामित्व प्रमाणित करने मे असफल रहता है तो यह भूमि उसके स्वामित्व से वापिस प्राप्त कर जी जावे। तथा प्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित 15 ऐयर भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। इस प्रकार के आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांत/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। वहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांत अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। जो खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि सम्वत 2008 के अपीलार्थी के रकबे की एवज मे भूमि एकीकरण मे कई नम्बरो मे से भूमि एकीकरण विभाग वालो ने दी थी जिसमे चारागाह का रकबा भी अपीलार्थी की खातेदारी मे दिया था जिसकी किस्म भी अपीलार्थी की खातेदारी मे दर्ज होने के बाद भी चारागाह दर्ज रखी है उसकी का फायदा उठाकर सेटलमेंट वालो ने अपीलार्थी की 15 ऐयर भूमि को चारागाह मे दर्ज कर दिया तथा तहसीलदार वामनवास सेटलमेंट की उक्त गलती पर ही अपीलार्थी को उसकी खातेदारी से बेदखल करने पर आसपास है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने आर आर डी 1994 मे अपने मत मे यह स्पष्ट किया है कि भूमि पूर्व मे खातेदारी मे थी लेकिन सेटलमेंट ने उसे चारागाह मे दर्ज कर दिया है तो ऐसी स्थिति मे लैण्ड होल्डर खातेदार को बेदखल नही कर सकता है। तथा राजस्व मंडल अजमेर द्वारा लैण्ड होल्डर के खिलाफ स्थगन जारी किया है। अपीलांत वृद्ध व्यक्ति है। वकील द्वारा समय पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही दी गई। अपीलांत का स्वास्थ्य ठीक होने पर वकील के पास जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.3.18 को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि ख0न0 73,74,162 मे स्थित अपीलार्थी की भूमि 0.15 है0 जो सेटलमेंट ने गलती से चारागाह मे दर्ज की है उसमे से अपीलार्थी को बेदखल नही करे, इसके बाबत रेस्पो0 को पाबन्द फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया है कि साबिक ख0न0 69 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा मे से 3 बीघा 10 विस्वा भूमि चारागाह की भूमि शामिल है। जो प्रारंभ से ही चारागाह के काम आती रही है। इस चारागाह की भूमि का खातेदारी इन्द्राज प्रार्थी/अपीलांत के हक मे एकीकरण के समय गलत अंकित हो गया। उक्त साबिक ख0न0 69 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा मे प्रार्थी की खातेदारी की तो मात्र 1 बीघा 9 विस्वा भूमि ही है जो जमाबंदी सम्वत 2019 से स्पष्ट है। जिसमे अनुसार प्रार्थी/अपीलांत को 35 ऐयर भूमि ही मिलनी चाहिए थी और इस 35 ऐयर


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

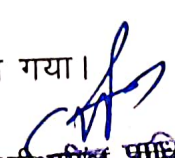
भूमि पर ही प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा है। शेष भूमि चारागाह है और चारागाह के काम आती है। चारागाह की भूमि की खातेदारी नहीं दी जा सकती है। चारागाह की भूमि का इन्द्राज खातेदारी किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलांट के हक में दर्ज की गई 1.09 है० में से 4 ऐयर भूमि कम की जाकर चारागाह में दर्ज किये जाने योग्य है। अपीलांट अतिक्रमण करने का आदि है। जिसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जाकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित भी किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा चाही गई रिलीफ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अब अपील पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी द्वारा चाही गई 15 ऐयर भूमि के अलावा शेष भूमि चारागाह से अतिक्रमण हटाने के निर्देश विधि के प्रावधानों के तहत ही दिये गये हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।



उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामने आये है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी एकीकरण सन 2018 ख०न० 69 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा में अपीलार्थीगण के पिता बृजलाल पुत्र रामपाल की खातेदारी में दर्ज है जिसके मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक वर्तमान सेटलमेंट में नये नम्बर 163 रकबा 1.09 है० कायम किये हैं। साविक की तुलना में अपीलार्थी को 0.15 है० रकबा कम दर्ज किया गया है। जिसे हाल ख०न० 74 रकबा 0.12 है० व ख०न० 73 रकबा 0.13 है० में 0.03 है० दर्ज करना पाया गया है। दौराने बहस वकील अपीलार्थीगण का कथन रहा कि खसरा न० 74 में पूर्वजों के समय से ही सिचाई के लिए कुआ भी बना हुआ है। चूँकि इन्द्राज दुरुस्ती का मामला अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, दावे में ही साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त यह तय होगा कि साविक खसरा न० 69 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा का 0.15 है० रकबा खसरा न० 74 रकबा 0.12 है० व खसरा न० 73 रकबा 0.13 है० में से 0.03 है० में गया है या नहीं। यह सभी बातें दावे में तय होनी हैं। पक्षकारान के मध्य वाद बाहुलता नहीं बढ़े इसके मद्देनजर दावे के निर्णय तक खसरा न० 74 रकबा 0.12 है० व खसरा न० 73 रकबा 0.03 है० की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु०न० 74/17 निर्णय दिनांक 27.3.18 को अपास्त किया जाता है। आराजी खसरा न० 74 रकबा 0.12 है० व खसरा न० 73 रकबा 0.03 है० वाले ग्राम कुआ गांव तहसील बामनवास की ताफैसला दावा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


राजस्थान (अपील अधिकारी)
राजस्थान (अपील अधिकारी)